

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57]

रायपुर, मंगलवार दिनांक 19 फरवरी 2013—माघ 30, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक एफ-157/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/132.—दिनांक 13 फरवरी, 2013 को नगर पंचायत दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छ.ग. के 2 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-157/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. श्री अर्जून कुंजाम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत, दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छ.ग.
2. श्री घासीराम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत, दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छ.ग.

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 13 फरवरी 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 26 मार्च 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है।
2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत दन्तेवाड़ा के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 4 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था। निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 26 मार्च 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत दन्तेवाड़ा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी श्री अर्जून कुंजाम एवं श्री घासीराम द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी श्री अर्जून कुंजाम एवं श्री घासीराम को दिनांक 8 अप्रैल 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जेवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई। उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण को विधिवत् तामील नहीं होने के कारण पुनः कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी श्री अर्जून कुंजाम एवं श्री घासीराम को दिनांक 30 अप्रैल 2012 को जारी की गई। उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों को दिनांक 17 मई 2012 को सम्यक् रूप से तामील की गई। कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण श्री अर्जून कुंजाम एवं श्री घासीराम को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि उक्त अभ्यर्थीगण को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है; उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
4. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परीशीलन किया गया। निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्री अर्जून कुंजाम एवं श्री घासीराम ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-ख का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :-

“धारा 32-क (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा — प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा।”

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :-

“धारा 32-ख निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल किया जाना — अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा।”

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्यिष्ट किया गया है। चूंकि 26 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश का दिन था; अतः उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने इसे अपने प्रतिवेदन में दिनांक 26 जनवरी 2012 उल्लेखित किया है।

5. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत दत्तेवाड़ा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों श्री अर्जून कुजाम एवं श्री घासीराम ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में आयोग को निर्धारित समयावधि में अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थियों श्री अर्जून कुजाम एवं श्री घासीराम प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिए कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं। तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों श्री अर्जून कुजाम एवं श्री घासीराम को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।
6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 13 फरवरी 2013 को जारी किया गया।

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)

राज्य निर्वाचन आयुक्त.

